



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

शाधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 34] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 1991/श्रावण 30, 1913  
No. 34] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 1991/SRAVANA 30, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

आन्ध्रा बैंक  
(कर्मचारी विभाग)

अधिसूचना

हैदराबाद, 29 जुलाई, 1991

स 666/3/ए.1/292 - बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं स्थानांतरण) अधिनियम 1980 (1980 का 40) के अनुच्छेद 12 के उप-अनुच्छेद (2) के साथ तत्तीय अनुच्छेद 19 में सेवन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आन्ध्रा बैंक का निदेशक मण्डल भारतीय रिजर्व बैंक को सलाह व केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से आन्ध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा नियमन, 1982 में शीर्ष संशोधन बनाने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

(2) लघु शीर्ष एवं आरम्भ :

(1) ये विनियम आन्ध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा संशोधन विनियम, 1991 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) आन्ध्रा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में

(क) विनियम 2 को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :

(1) ये विनियम आन्ध्रा बैंक के सभी अधिकारियों पर लागू होते हैं तथा बैंक के ऐसे अन्य कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं, जिन पर मक्षम, अधिकारी आवश्यक समझते हों तथा ये विनियम उन शर्तों पर लागू होंगे जो इस प्रकार के अधिकारी निर्धारित करेंगे।

(2) मक्षम अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से या सामान्य रूप से किये गये निर्धारण के मामलों का छोड़कर अन्य मामलों में भारत के बाहर स्थानांतरित/तैनात/प्रतिनियुक्त अधिकारियों को भी ये लागू होंगे।

(3) तो भी ये विनियम भारत के बाहर किसी भी देश में नियुक्त/कार्यरत या स्थायी रूप से सेवागत कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

(क) विनियम 3 (एल) और 3 (एम) को निम्नप्रकार से पढ़ा जाए,

3(एल) "वेतन" अर्थात् गत्यावरोध वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन

3(एम) "वेतन" अर्थात् कुल वेतन और महंगाई भत्ता।

(ग) विनियम 4(1) को निम्नानुसार से पढ़ा जाए :

दिनांक 01-02-1984 को तथा उसके बाद से अधिकारियों के लिए प्रत्येक श्रेणी के अग्रे सूचित वेतन-मान सहित निम्नलिखित चार श्रेणियां होगी :

- (क) उच्च कार्यपालक श्रेणी :  
 वेतनमान VII -र. 4100-125-4600  
 वेतनमान VI र. 3850-125-4350
- (ख) वरिष्ठ प्रबन्ध श्रेणी :  
 वेतनमान V र. 3575-110-3685-115-3800  
 वेतनमान IV र. 2925-105-3450
- (ग) मध्य प्रबन्ध श्रेणी :  
 वेतनमान III र. 2650-100-3250  
 वेतनमान II र. 1825-100-2925
- (घ) कनिष्ठ प्रबन्ध श्रेणी :  
 वेतनमान I र. 1175-60-1475-70-1895 ई.बी. 95-  
 2275-100-2675

01-11-1987 को तथा उसके बाद से प्रत्येक श्रेणी के विरुद्ध विनि-  
 श्चिष्ट वेतनमान निम्न प्रकार होंगे :

- (क) उच्च कार्यपालक श्रेणी :  
 वेतनमान VII र. 6100-150-7000  
 वेतनमान VI र. 5950-150-6550
- (ख) वरिष्ठ प्रबन्ध श्रेणी :  
 वेतनमान V र. 5350-150-5950  
 वेतनमान IV र. 4520-130-4910-140-5050-150-5350
- (ग) मध्य प्रबन्ध श्रेणी :  
 वेतनमान III र. 4020-120-4260-130-4910  
 वेतनमान II र. 3060-120-4260-130-4390
- (घ) कनिष्ठ प्रबन्ध श्रेणी :  
 वेतनमान I र. 2100-120-4020

बशर्ते कि नियुक्ति की तारीख के समय लागू वेतनमानों द्वारा  
 नियंत्रित प्रत्येक अधिकारी, जिसका विनियम 8 के अन्तर्गत सरकार द्वारा  
 जारी किये गये मार्गदर्शनों के अनुसार उक्त वेतनमानों में निर्धारण करना  
 है उक्त वेतनमानों में उक्त निर्धारण सरकार के मार्गदर्शनों के अनुरूप  
 किया जाएगा ।

(घ) विनियम 5(1) के निम्नप्रकार से पढ़ा जाए : 01-11-1987  
 को और उसके बाद से वेतन वृद्धियाँ निम्नलिखित उप-खण्डों के अधीन  
 दी जाएंगी :

(क) विनियम 4(1) में दिये गये वेतनमानों में विनिश्चिष्ट वेतन-  
 वृद्धियाँ मध्य अधिकारी की स्वीकृति होने पर वार्षिक आधार पर होंगी  
 और वे जिस महीने में देय होती हैं, उस महीने की पहली तारीख को दी  
 जाएंगी ।

(ख) वेतनमान I तथा II के अधिकारियों को अपने सम्बन्धित  
 वेतनमानों में अधिकतम चरण तक पहुँचने के पश्चात् वक्षता-रोध पाए करने  
 पर नीचे विनिश्चिष्ट "ग" के अनुसार केवल अगले उच्च वेतनमान में  
 गत्यावरोध वेतनवृद्धि महिन और वेतनवृद्धि दी जाएगी ।

(ग) उपर्युक्त "ख" के अधिकारियों सहित जोकि एम. एम. जी.  
 वेतनमान II तथा III के अधिकतम चरणों में पहुँच गये हैं, वेतनमान II  
 अथवा III के अंतिम चरण में पहुँचने के पश्चात् सेवाकाल के प्रत्येक 3  
 पूर्ण वर्षों हेतु गत्यावरोध वेतनवृद्धि लेंगे, जैसा भी मामला हो, बशर्ते कि  
 वेतनमान II के अंतिम चरण में अधिकारियों हेतु अधिकतम र. 130/-  
 प्रत्येक की 2 ऐसी वेतनवृद्धियाँ हो तथा वेतनमान-II के अंतिम चरण में  
 अधिकारियों हेतु र. 140/- की ऐसी एक वेतनवृद्धि हो ।

टिप्पणी : अगले उच्च वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धियों को मंजूरी  
 मतलब पदोन्नति नहीं है । ऐसी वेतनवृद्धियाँ देने के पश्चात् भी अधिकारी  
 विशेषाधिकार, अनुलाभ, कर्तव्यों दायित्वों, अथवा अपने मूलभूत वेतनमान-II  
 अथवा II के पदों, जैसा भी मामला हो, हेतु पात्र होंगे ।

(ब) विनियम 5(2) की निम्नप्रकार से पढ़ा जाए : निम्न विधि  
 को तथा उस विधि से सी.एस.आई.आई.बी. का प्रत्येक भाग उत्तीर्ण  
 करने पर वेतनमान में एक प्रतिशत वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी ।

दिनांक 01-11-1987 को तथा उस दिनांक से जो अधिकारी वेतन-  
 मान के अधिकतम चरण में पहुँचने हैं अथवा पहुँच चुके हैं तथा मित्राय  
 पदोन्नति के और आगे नहीं जा सकते हैं, सरकार के मार्गदर्शनों का शर्मा  
 के अधीन यदि हों, सी.एस.आई.आई.बी. परीक्षा उत्तीर्ण करने पर  
 प्रतिशत वेतनवृद्धि के बढ़ने में आवश्यक शैक्षिक भत्ता निम्न अनुसार  
 दिया जाएगा ।

जिनमें सी.एस.आई.आई.बी. का : एक वर्ष के पश्चात् र. 100/- प्र-  
 केवल प्रथम भाग उत्तीर्ण किया है । माह जिसमें से र. 75/- अधिवर्षित  
 लाभ के लिए है ।

जिनमें सी.एस.आई.आई.बी. (i) : एक वर्ष के पश्चात् र. 100/-  
 दोनों भाग उत्तीर्ण किये हैं प्रति माह जिसमें से र. 75/- अधि-  
 वर्षित लाभ के लिए है ।  
 : (ii) 2 वर्ष के पश्चात् र. 250/-  
 प्रतिमाह जिसमें से र. 200/-  
 अधिवर्षित लाभ के लिए है ।

टिप्पणी :—यदि शैक्षिक योग्यता भत्ता देने वाले किसी अधिकारी  
 को अगले उच्च वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो उसे ऐसे उच्चतम  
 वेतनमान में निर्धारण के पश्चात् वेतनमान में उपर्युक्त वेतनवृद्धि का सीमा  
 तक सी.एस.आई.आई.बी. उत्तीर्ण करने हेतु प्रतिशत वेतनवृद्धियाँ/  
 प्रदान की जाएंगी तथा यदि वेतनमान में कोई वेतनवृद्धि उपलब्ध नहीं है  
 अथवा एक ही वेतनवृद्धि उपलब्ध है तो अधिकारी वेतनवृद्धियों के बढ़ने  
 में शैक्षिक योग्यता भत्ते हेतु पात्र होगा ।

(छ) विनियम 21 की निम्नप्रकार से पढ़ा जाए :

दिनांक 01-11-1987 को तथा उस दिनांक से महंगाई भत्ता योजना  
 निम्न प्रकार से होगी :

(1) महंगाई भत्ता अग्रिम भारतीय औषध प्रमित वर्ग उपभोक्ता  
 मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के निमाही  
 औषध में 600 अंकों के ऊपर 4 अंक का प्रत्येक वृद्धि अथवा  
 गिरावट के हिसाब से देय होगा ।

(2) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :

- (1) र. 2500/- तक "वेतन" का 0.67 प्रतिशत, और  
 (2) र. 2500 से ऊपर परन्तु र. 4000/- तक "वेतन" का 0.55  
 प्रतिशत और  
 (3) र. 4000/- से ऊपर परन्तु र. 4260/- तक "वेतन" का 0.33  
 प्रतिशत और  
 (4) र. 4260 से ऊपर "वेतन" का 0.17 प्रतिशत

(ग) विनियम 22(1) की निम्नप्रकार से पढ़ा जाए

1-11-1987 को और उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक  
 द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो उससे उक्त वेतनमान  
 के प्रथम प्रक्रम का 6 प्रतिशत अथवा अवाप्त के निम्न मानक  
 किराया, इनमें से जो भी कम हो, देय किया जाएगा ।

(घ) विनियम 22(2) की निम्न प्रकार से पढ़ा जाए ।

01-01-1990 को और उसके बाद से यदि अधिकारी को बैंक द्वारा मकान नहीं दिया गया है, तो वह निम्नलिखित वर्गों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा :

कालम 1 कार्यरत स्थान के अनुरूप	कालम 2 देय मकान किराया भत्ता
(1) समय-समय पर सरकार के मार्गदर्शक सूची तथा "क" ग्रुप के प्रोजेक्ट क्षेत्र केन्द्रों के आधार पर "क" श्रेणी वाले प्रमुख शहर।	हर महीने के वेतन का 14 प्रतिशत या अधिकतम रु. 450/-
(2) क्षेत्र-1 तथा ग्रुप "ख" के प्रोजेक्ट क्षेत्र केन्द्रों में अन्य स्थान।	हर महीने के वेतन का 12 प्रतिशत या अधिकतम रु. 375/-
(3) क्षेत्र 2 और राज्य को राज-श्रानियां व संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियां, जो उपर्युक्त (1) एवं (2) में शामिल नहीं हैं।	हर महीने के वेतन का 10 प्रतिशत या अधिकतम रु. 325/-
(4) क्षेत्र 3	हर महीने के वेतन का 8 प्रतिशत या अधिकतम रु. 300/-

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किटाण को स्वीकृत प्रस्तुत करे तो उसे दिया जाने वाला मकान किराया भत्ता, अन्यथा देय अधिकतम मकान किराया भत्ते का अधिकतम 175 प्रतिशत सहित उनके वेतनमान के प्रथम चरण में वेतन के 6 प्रतिशत से अधिक उनके आवासोपय स्थान हेतु उसे दिया गया वास्तविक किराया होगा।

(1) विनियम 23(3) निम्न लिखित अनुसार होगा : जहाँ अधिकारी अपने घर में रहता है वह उपविनियम (2) में उल्लिखित नियम के आधार पर सामान्य मकान किराया भत्ता प्राप्त करने को योग्यता रखता है, जैसे कि वह प्रति माह निम्नलिखित "क" या "ख" की अधिकतम राशि के 1/12 हिस्सा मासिक किराये के रूप में भरा कर रहा है।

"क"

(1) आवास से संबंधित देय नगरपालिका कर, और

(2) भूमि के मूल्य सहित आवास के पूंजीगत मूल्य का 12 प्रतिशत और यदि आवास किसी भवन का हिस्सा हो तो उस आवास के लिए विशेष फिक्सचर्स जैसे एयर कंडीशनर्स को छांड़कर, उपर्युक्त भूमि के पूंजीगत मूल्य का अनुपातिक हिस्सा।

"ख"

आवास का नगरपालिका द्वारा निर्धारण हेतु लिया गया वार्षिक किराया मूल्य

स्पष्टीकरण :-

(1) इस विनियम हेतु "मानक किराया" का अर्थ है :-

(क) बैंक के अपने आवास के मामले में, सरकार से लागू ऐनों गणना हेतु लागू पद्धति के अनुसार परिकल्पित मानक किराया।

(ख) दि. 1-4-1990 से महा बैंक ने आवास किराये पर लिया है, बैंक द्वारा देय सविश्वस्य किराया या उपर्युक्त (क) पद्धति के अनुसार परिकल्पित किराया जो भी कम हो।

(2) इस विनियम और विनियम 23 से 1, क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3 का अर्थ निम्नलिखित होगा :-

क्षेत्र 1 :- 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान

क्षेत्र 2 :- क्षेत्र 1 में शामिल शहरों के अतिरिक्त अन्य सभी शहर जिन्होंने प्रत्येक एक लाख और उससे अधिक हैं।

क्षेत्र 3 :- सभी शहर जो क्षेत्र 1 व क्षेत्र 2 में सम्मिलित नहीं हैं।

(विनियम 23(i) निम्नलिखित अनुसार होगा :-

दि. 01-11-1987 से, यदि वह नाथे दो गैर सरणी के कालम 1 में वर्णित स्थान पर कार्यरत हैं, तो उस स्थान पर कालम 2 में वर्णित दर पर रा.सं.ए. दिया जायेगा, बशर्ते कि शहरी पणजी व मारमुगोथा को छोड़ गोवा राज्य के स्थानों पर सी.सी.ए. जहाँ वह 1-11-1987 को देय न हो, 20-6-1988 से देय होगा।

स्थान	दर
1	2
(क) क्षेत्र 1 तथा गोवा राज्य के स्थान	हर महीने मूल वेतन का 6 1/3 प्रतिशत या अधिकतम रु. 220/-
(ख) ऐसे स्थान जहाँ पर 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या हो और, राज्य के राजधानी व चंडीगढ़, पॉन्डिचेरी और पॉर्ट ब्लेयर जो उपर्युक्त "क" में न हों	हर महीने मूल वेतन का 4 प्रतिशत या अधिकतम रु. 135/-

विनियम 23(5) निम्न अनुसार होगा :-

(ग) दि. 01-11-1987 से, यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर कहीं प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो वह जिस पद के लिए प्रतिनियुक्त किया गया उस पद से संबद्ध सभी परिलब्धियां प्राप्त कर सकता है। दूसरी ओर वह अपने वेतन के अतिरिक्त 12 प्रतिशत, अधिकतम रु. 750/- प्रतिनियुक्त भत्ता एवं ऐसे अन्य भत्ते जो वह बैंक को सेवा में आह्वित करता रहा, प्राप्त करेगा।

व्यवस्था की गई है कि जिस सप्ताह में वह प्रतिनियुक्त किया गया हो, वह उग्रा स्थान पर हो जहाँ कि प्रतिनियुक्ति के पहले उसे पास्ट किया गया हो तो वह अपने वेतन का 6 प्रतिशत अधिकतम रु. 350/- प्रतिनियुक्त भत्ते स्वरूप प्राप्त करेगा।

यह भी किसी अधिकारी के बतौर सकास गुरुय बैंक के प्रशिक्षण संस्थान अथवा सीएमआर बी में प्रतिनियुक्ति पर होने, पर वह वेतन के 6 प्रतिशत अधिकतम रु. 350/- प्रतिनियुक्त भत्ते हेतु पात्र होगा।

(घ) विनियम 23(6) निम्न अनुसार होगा :-

दि. 01-11-1987 से यदि वह किसी पद पर उच्चतर वेतनमान में 7 दिनों से कम नहीं या कैलेंडर वर्ष के कुल 7 दिनों के दौरान की लम्बा अवधि के लिए एक बार स्थानापन्न किया जाता है, तो उसे स्थानापन्न भत्ते के रूप में वेतन का 6 प्रतिशत अधिकतम रु. 250/- प्रतिमाह, स्थानापन्न भत्ते के रूप में प्राप्त होगा। स्थानापन्न भत्ता भविष्य निधि के लिए ही देय है अन्य निमित्त नहीं।

व्यवस्था की गई है कि जहाँ एक अधिकारी उच्चतर वेतन में स्थानापन्न होता है, विनियम 6 के अन्तर्गत पदों के वर्गीकरण के पुनः निरीक्षण के उमे एक वर्ष की अवधि के लिए स्थानापन्न भत्ता नहीं मिलेगा जिस सप्ताह में यह पदों के वर्गीकरण का पुनः निरीक्षण प्रभावी है।

(च) विनियम 23(7) निम्न अनुसार होगा :-

"वित्तीय वर्ष 1989-90 को तथा से, वह ऐसी शाखा में नियुक्त है, जहाँ बहियों 31 मार्च व 30 सितम्बर को बंद कर दी जाती है, प्रत्येक 2 समापन हेतु रु. 150/- समापन भत्ता प्रदान किया जायेगा।

(घ) विनियम 23(10) निम्न अनुसार होगा :—

दि. 01-11-1987 को तथा से, यदि वह निम्न सागणा के कालम 1 में वर्णित किसी स्थान पर कार्यरत है तो उसे कालम 2 में वर्णित दर पर पहाड़ी एवं ईंधन भत्ता दिया जायेगा.

स्थान	दर
1	2
(1) 1000 मीटर तथा अधिक वेतन का 5 प्रतिशत बर्णन कि ऊंचाई वाले परन्तु 1500 मीटर से अधिकतम रु. 130/- कम ऊंचाई वाले स्थान तथा सरकारा शहर	
(2) 1500 मीटर तथा अधिक वेतन का 6 1/2 प्रतिशत बर्णन कि ऊंचाई वाले परन्तु 3000 मीटर से अधिकतम रु. 160/- कम ऊंचाई वाले स्थान	
3) 3000 मीटर तथा अधिक वेतन का 15 प्रतिशत बर्णन कि ऊंचाई वाले स्थान अधिकतम रु. 600/-	

टिप्पणी. (क) 750 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर नियुक्त अधिकारी, जोकि अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों से घिरे हैं, तथा जहां तक 1000 मीटर तथा अधिक ऊंचाई पर कि बिना नही पहुंचा जा सकता, उन्हें पहाड़ी तथा ईंधन भत्ता 1000 मीटर तथा अधिक ऊंचाई वाले केन्द्रों पर देय दर के अनुसार दिया जायेगा।

(ख) किसी भी केन्द्र पर उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार वर्तमान में दिये जाने वाले पहाड़ी तथा ईंधन भत्ते को बदल दिया जा रहा है। वि. 1-11-1987 में 30-4-89 के बीच पहले ही दिये गये भत्ते सम्मिलित नहीं होंगे। दि. 01-05-1989 से पुराने प्रावधानों के अन्तर्गत 10 अप्रैल तक दिये गये भत्ते को प्रमात्रा का ही उभे, वेतनमान में उभे केन्द्र पर नियुक्ति तक उस तिथि से पूर्व अथवा को उस केन्द्र पर नियुक्त अधिकारियों के मामले में सुरक्षा प्रदान का जायेगी।

(ग) विनियमन 24(1) को निम्न रूप में पढ़ा जाये :—

निम्नांकित के आधार पर एक अधिकारी स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों को चिकित्सा के लिये उनके द्वारा वास्तव में किये हुए (चिकित्सा) व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का योग्यता रखता है अर्थात् :—

(क) चिकित्सा व्यय :—

01-01-1990 को और उससे बाद एक अधिकारी को स्वयं या अपने परिवार हेतु नीचे वा गये सागणा के कालम 1 में उल्लिखित वेतन श्रेणी में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का जायेगी जो कि उससे स्वयं के इस घोषणा करने पर होगी कि उसने ऐसा व्यय किया है। इसके साथ ही दावे की राशि हेतु खाते को विश्वरणी गैसल का जाये बशर्त कि कालम 2 में विनिश्चिष्ट सीमा को पूरा हो।

सारणी

वेतन सीमा	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
रु. 2100/- से रु. 3060/- प्र.म. --रु. 750/-	
रु. 3061/- प्र.मा. और उससे अधिक--रु. 1,000/-	

टिप्पणी :—अनुपयुक्त चिकित्सा राशि, जो अधिकारी मौखिक कर सकता सकता है परन्तु मौखिक किसी भी समय उल्लिखित अधिकतम राशि तीन गुणा से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :—

इस विनियम के प्रयोजन के लिये अधिकारी के "परिवार" में उसका पति उसकी पत्नी, पूर्णतः आश्रित संतान तथा पूर्णतः आश्रित माता-पिता ही शामिल होंगे।

(ख) अस्पताल में भर्ती खर्च :

(1) दिनांक 1-4-1989 को तथा उससे अधिकारी के मामले में 90 प्रतिशत तक और उसके परिवार जनों के सभी मामलों, जहां अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है, में 60 प्रतिशत तक अस्पताल व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। बिल, वाउचर आदि के आधार पर व्यय की प्रतिपूर्ति, सरकार द्वारा समय-समय पर जारीकृत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अधिकतम राशि होगी।

(2) अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों (यथा मामलातुसार) से अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी या म्युनिसिपल अस्पताल या किसी प्राइवेट अस्पताल या किसी दूसरे के प्रबंधन में अस्पताल घमोर्षे सस्था अथवा धार्मिक संस्था में भर्ती हों। किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारी या उनके परिवार के सदस्य या दोनों किसी अनुमोदित नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। फिर भी ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति ऐसी राशि तक सीमित होगी चाहे जो उपरिलिखित किसी एक अस्पताल में रोगी के भर्ती होने के मामले में प्रतिपूर्ति योग्य होती।

(3) 01-04-1989 को तथा उससे निम्नलिखित रंगों के मध्य में, जिन्हे बैंक के चिकित्सा अधिकारी तथा मान्यता प्राप्त अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित आवासीय इलाज की आवश्यकता है, उन्हें अस्पताल व्यय माना जायेगा तथा अधिकारी के मामले में 90 प्रतिशत तक तथा उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 60 प्रतिशत तक उसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी।

कैम्पर, टी बी, पैरालिसिस, कॉडियाक एलमेंट, ट्यूमर, चेचक, 1. म्यूरीसी, डिफीरिया, मेपरसी, किडनी एलमेंट।

(विनियम 25) निम्न प्रकार पढ़ा जाये :—

"1-11-1987 को तथा उससे कोई भी अधिकारी बैंक द्वारा आवास स्थान की व्यवस्था हेतु हकदार होगा। फिर भी, बैंक चाहे तो अधिकारी के वेतनमान, जिसमें उसे नियुक्त किया गया है, के प्रथम चरण के 6 प्रतिशत या आवास हेतु मानक किया, जो भी कम हो, लेकर उसके लिये आवास की व्यवस्था कर सकता है। ऐसे आवास में यदि फर्नीचर प्रदान किया गया तो बैंक अधिकारी के वेतनमान के प्रथम चरण में 1 1/2 प्रतिशत के सम-राशि धमूल करेगा। जहां बैंक द्वारा ऐसा आवास स्थान की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पर, बिजली, पानी, गैस तथा सफाई व्यवस्था का खर्च अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(विनियम 33(4) निम्न प्रकार पढ़ा जाये :—

"01-01-1990 को तथा उससे जहां अधिकार छुट्टी के लिये आवेदन दिया गया तथा उसे रु. 24 किया गया इसे छोड़कर अधिकार छुट्टी 240 दिनों तक जमा की जा सकती है।"

(विनियम 34(1) निम्न प्रकार पढ़ा जाये :—

01-01-1989 को तथा उससे, एक अधिकारी अपनी सेवा के पूरे हुए प्रत्येक वर्ष में 30 दिनों, बशर्तकि पूरी सेवा के दौरान 18 महीने की अधिकतम अवधि हो की बीमारी छुट्टी लेने का पात्र होगा। पूरी सेवा के दौरान 540 दिनों तक ऐसी छुट्टी जमा की

जा सकती है तथा बैंक द्वारा गान्ध अथवा बैंक द्वारा अपनी लागत पर उसके विवेकाधिकार के अनुसार नामांकित चिकित्सक द्वारा जारी कृत चिकित्सा प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर ही वह छुट्टी प्रयुक्त की जा सकती है।

(नियम 35 निम्न प्रकार पढ़ा जाये ---

01-01-1989 का तथा उससे जहाँ अधिकारी ने 35 वर्ष की सेवा पूरी की है, वह 24 वर्षों से अधिक से सेवा काल के प्रत्येक वर्ष हेतु एक महीने के हिसाब से, अनिश्चित बीमारी छुट्टी, बर्तन कि तीन महीनों को अधिकतम अवधि की अनिश्चित बीमारी छुट्टी का लेन हेतु योग्य होगा।

(नियम 41 निम्न प्रकार पढ़ा जाए ---

01-07-1989 तथा उससे जब कभी किसी अधिकारी से अपेक्षित है कि वह ड्यूटी पर यात्रा करे निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे।

- (1) (i) कनिष्ठ प्रबंधन का कोई अधिकारी रेलगाड़ी को पहली श्रेणी या वातानुकूल गहनयान द्वारा यात्रा कर सकता है। फिर भी व्यापार की अनिवार्यता या, अन्ततः के हित को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिए जाने पर वह हवाई जहाज (एकानर्मी श्रेणी) में यात्रा कर सकता है।
- (ii) मध्यम प्रबंधन श्रेणी का कोई अधिकारी रेलगाड़ी को पहली श्रेणी या वातानुकूल गहनयान द्वारा यात्रा कर सकता है। फिर भी, व्यापार की अथवा की दूरी 500 कि.मी. से अधिक हो तो वह हवाई जहाज (एकानर्मी श्रेणी) में यात्रा कर सकता है। फिर भी, व्यापार या अनिवार्यता या जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दिये जाने पर वह कम दूरी के लिए भी हवाई जहाज में यात्रा कर सकता है।
- (iii) बरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का कोई अधिकारी रेलगाड़ी की वातानुकूल प्रथम श्रेणी या हवाई जहाज (एकानर्मी श्रेणी) में यात्रा कर सकता है।
- (iv) कनिष्ठ प्रबंधन अथवा उच्च पालक श्रेणी का कोई अधिकारी का द्वारा यात्रा कार्य कर सकता है यदि वह स्थान रेल या हवाई मार्ग से न जुड़ा हुआ हो। बर्तन कि इसकी दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो। फिर भी, जहाँ दो स्थानों के बीच यात्रा की अधिकतम दूरी वायुमार्ग या रेल द्वारा तय किए जाने पर शेष दूरी को सामान्यतया कार द्वारा तय किया जाना चाहिए।
- (v) व्यापार की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी किसी भी अधिकारी को स्वयं या वाहन द्वारा या बैंक के वाहन द्वारा यात्रा करने का प्राधिकार दे सकता है।
- (2) (i) हवाई या रेल द्वारा यात्रा करने पर अधिकारी को एक ओर के भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (ii) सड़क मार्ग से निर्जल वाहन द्वारा यात्रा करने पर, समय समय पर वाहन के प्रकार की उपयोग किया जाना किए गए व्यय तथा तय की गई दूरी पर निर्भर होगा, किलोमीटर आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो बैंक द्वारा तय की जाएगी।
- (iii) जहाँ टैक्सी किराए पर लेने की अनुमति दी गई है वह वास्तविक टैक्सी प्रभार की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (iv) परिवहन मोटर या जल परिवहन द्वारा यात्रा किए जाने पर वास्तविक भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- (3) परिवहन एवं आरिक्त बोटा गई मजदूरी के वास्तविक खर्च का प्रतिपूर्ति का जाएगी।

(4) 1-1-1987 का तथा से निम्न प्रस्तुत सारणी में तालिम 1 में बताई गई श्रेणी के तालिम 2 में बताए गए पदों द्वारा पर विराम करने के पात्र होंगे।

सारणी

श्रेणी/वर्तमान के अधिकारी	क श्रेणी के बड़े शहर	अथ 1	अथ 2 या 3
वर्तमान VI एवं VII	100 00	80 00	60 00
वर्तमान IV एवं V	100 00	80 00	60 00
वर्तमान II एवं III	70 00	60 00	50 00
वर्तमान I	70 00	60 00	50 00

बर्तन कि

(क) जहाँ अनुपस्थिति की कुछ अवधि 4 घंटे से कम है परन्तु 4 घंटे से अधिक है तब तक के आधे रात पर विरामस्थान का भुगतान किया जाएगा।

(ख) विभिन्न श्रेणियों/वर्तमान के अधिकारियों को निम्नलिखित दर्शाई गई सीमा तक आईटीसी होटल के एकल कमर के आवासीय प्रभार तक की वास्तविक होटल खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

श्रेणी/अधिकारी के वर्तमान	ठहरने की पावना	बोर्डिंग चार
		“क” श्रेणी के बड़े शहर
वर्तमान VII एवं VI	4+ होटल	100 00 80 00 60 00
वर्तमान IV एवं V	3+ होटल	100 00 80 00 60 00
वर्तमान II एवं III	2+ होटल (गैर वातानुकूलित)	70 00 60 00 50 00
वर्तमान I	1+ होटल (गैर वातानुकूलित)	70 00 60 00 50 00

(ग) विराम स्थान पर जहाँ निशुल्क बोर्डिंग की व्यवस्था की गई है, विराम करने का तीन चौथाई स्वाकार्य होगा।

(घ) विराम स्थान पर जहाँ निशुल्क बोर्डिंग की व्यवस्था की गई है, विराम करने का आधा स्वाकार्य होगा।

(ङ) जहाँ निशुल्क बोर्डिंग एवं आरिक्त की गई हो, विराम करने का एक चौथाई स्वाकार्य होगा।

(च) सभी निरीक्षण अधिकारियों का हैडक्वार्टर से बहार निरीक्षण ड्यूटी पर प्रति दिन रु 10 का अनुपूरक डियम मत्ता भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण

“प्रति डियम” विराम भत्ता परिकल्पित हेतु, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसका कोई भाग, हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान हेतु रिपोर्टिंग समय से एक अन्य मामले के प्रस्थान के निर्धारित समय से आगमन के वास्तविक समय तक गणना की जाएगी। जहाँ कुल अनुपस्थिति की अवधि 24 घंटे से कम है प्रति डियम करने 8 घंटे से कम मर्यादित नहीं होगा।

विनियम 12(2) (1) को निम्नरूप में पढ़ा जाए --

"1-11-1987 को तथा से स्थानांतरणाधीन अधिकारी अपने सामान को भाग गार्डी द्वारा भेजने पर, निम्नलिखित सीमा तक उनके खर्च का प्रतिपूर्ति की जाएगी।

वेतन सीमा	जहां उनका परिवार है	जहां उनका कोई परिवार नहीं है
रु. 2100/- प्रति माह से रु. 3060/- प्रति माह तक	2000 कि मी	1000 कि मी
रु. 3061/- प्रति माह एवं उससे अधिक	संपूर्ण वेतन	2000 कि मी

(ज) विनियम 12(4) का निम्नरूप में पढ़ा जाए --

"किसी स्थान की अधिकार के स्थानांतरण होने पर, यात्रा पर हुई अवाध हेतु बीमा के समान धन पर विराम भत्ता दिया करने का प्राव्य होगा।

अर्थात् कि 30-10-1987 से जहां बैंक द्वारा अधिकारों का निष्पत्ति क नए स्थान पर किसी भी आवासन सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है और जहां ऐसे अधिकारों कार्यप्रणाली की प्रक्रिया में, अपने नियंत्रण से बाहर कारणों से अतिरिक्त खर्च कर सकता है, सक्षम प्राधिकारों, योग्यतानुसार 15 दिनों का अवधि तक, या उन्हें आन स उपलब्ध करने के समय तक, जो भी शीघ्र हो, विराम भत्ता भुगतान कर सकता है।"

(घ) विनियम 45(2) निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए --

बैंक समय-समय पर आवश्यक निधि के नियमों के अनुसार वार्षिक निधि को अंशदान देगा अर्थात् कि अंशदान की गई राशि, 1-11-1987 से 31-12-1988 तक अधिकारों के 80 प्रतिशत वेतन का 10 प्रतिशत, 1-1-1989 से 31-12-1979 तक 90 प्रतिशत वेतन का 10 प्रतिशत एवं 1-1-1990 को तथा से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

विनियम 46(2) निम्नरूप में पढ़ा जाए --

अधिकारों को प्रत्येक समान वर्ष का सेवा के एक सहोदना का वेतन, अधिकतम 15 महीने के वेतन तक उपदान की राशि का भुगतान किया जाएगा।

अर्थात् कि जहां अधिकारों ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा समाप्त कर ली है, उसे तीन संपूर्ण वर्षों की सेवा समाप्त करने पर प्रत्येक सहोदना के वेतन का अतिरिक्त देकर गुना अतिरिक्त राशि का प्राव्य होगा।

टिप्पणी, यदि सहायक का अंश संपूर्ण वर्ष का सेवा से 6 महीने या उससे अधिक है उपदान उस अंशधन के समानुपातिक रूप पर भुगतान किया जाएगा।

एम गोपात्रकुण्डल्य, सहायक प्रबन्धक (का)

ANDHRA BANK

(Staff Department)

NOTIFICATION

Hyderabad, the 29th July, 1991

No. 666/3/A-1/292.—In exercise of powers conferred by Section 19 read with Sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Andhra Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Andhra Bank (Officers') Service Regulations, 1982.

(2) Short title and commencement.—(1) These regulations may be called Andhra Bank (Officers') Service Amendment Regulations, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) In the Andhra Bank (Officers') Service Regulations, 1982,—

(a) Regulation 2 shall read as under :

(1) These regulations shall apply to all Officers of the Bank and such other employees of the Bank to whom they may be made applicable by the Competent Authority to the extent and subject to such conditions as such authority may decide.

(2) They shall also apply to officers transferred/posted/deputed outside India except to such extent as may be specifically or generally prescribed by the Competent Authority.

(3) They shall, however, not apply to employees appointed/engaged in any country outside India and permanently serving there.

(b) Regulation 3(1) and (m) shall read as under :

3(1) "pay means basic pay including stagnation increment.

3(m) "salary" means the aggregate of the pay and dearness allowance

(c) Regulation 4(1) shall read as under :

"On and from 01-02-1984, there shall be the following four grades for officers with the scale of pay specified against each of the grades :—

(a) Top Executive Grade :  
Scale VII Rs. 4100-125-4600  
Scale VI Rs. 3850-125-4350

(b) Senior Management Grade :  
Scale V Rs. 3575-110-3685-115-3800  
Scale IV Rs. 2925-105-3450

(c) Middle Management Grade :  
Scale III Rs. 2650-100-3250  
Scale II Rs. 1825-100-2925

(d) Junior Management Grade :  
Scale I Rs. 1175-60-1475-70-1895-EB-95-2275-100-2675

On and from 01-11-1987, the scales of pay specified against each grade shall be as under :—

(a) Top Executive Grade :  
Scale VII Rs. 6400-150-7000  
Scale VI Rs. 5850-150-6550

(b) Senior Management Grade :  
Scale V Rs. 5350-150-5950  
Scale IV Rs. 4520-130-4910-140-5050-150-5350

(c) Middle Management Grade :  
Scale III Rs. 4020-120-4260-130-4910  
Scale II Rs. 3060-120-4260-130-4390

(d) Junior Management Grade :  
Scale I Rs. 2100-120-4020

Provided that every officer who is governed by the scale of pay as in force on the appointed date having been fitted into the said scale of pay in accordance with the guidelines of the Government issued under Regulation 8, shall be fitted in the scale of pay set out above in accordance with the guidelines of the Government.

(d) Regulation 5(1) shall read as under :

"On and from 01-11-1987 the increments shall be granted subject to the following sub-clauses :—

(a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation 4(1) shall, subject to the

sanction of the Competent Authority, accrue on the annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

- (b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar.

- (c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs. 130 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 140 for officers in the last stage of Scale III.

Note.—Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

- (e) Regulation 5(2) shall read as under :

"An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of Certificated Associate of Indian Institute of Bankers Examination on or after the appointed date.

On and from 01-11-1987 officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under :—

Those who have passed only Part I of CAIIB Rs. 100/- p.m. after one year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.

Those who have passed both parts of CAIIB : (i) Rs. 100/- p.m. after 1 year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits  
(ii) Rs. 250/- p.m. after 2 years, of which Rs. 200/- shall rank for superannuation benefits.

Note.—If an officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).

- (f) Regulation 21 shall read as under :

"On and from 01-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

- (i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

- (ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

- (i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 2500 plus,  
(ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 2500 to Rs. 4000 plus,  
(iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 4000 to Rs. 4260 plus,

- (iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4260.

- (g) Regulation 22(1) shall read as under :

"On and from 01-11-1987, where an officer is provided with residential accommodation by the bank, 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

- (h) Regulation 22(2) shall read as under :

"On and from 01-01-1990, where an officer is not provided any residential accommodation by the bank he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates :—

Column I Where the place of work is in	Column II HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'.	14% of the pay subject to a maximum of Rs. 450/- p.m.
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	12% of the pay subject to a maximum of Rs. 375/- p.m.
(iii) Area II and state capitals and capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above	10% of the pay subject to a maximum of Rs. 325/- p.m.
(iv) Area III	8% of the pay subject to a maximum of Rs. 300/- p.m.

provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or at the rates indicated in Column II with a maximum of 175% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise whichever is lower.

- (i) Regulation 22(3) shall read as under :

"Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to sub-regulation (2) as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of A or B below :

#### A

The aggregate of :—

- (i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation ; and  
(ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners or

#### B

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation  
Explanation :—

- (1) For the purpose of this Regulation "standard rent"

means :—

(a) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government ;

(b) With effect from 01-04-1990 where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure in (a) above, whichever is lower.

(2) In this Regulation and in Regulation 23 Area I, Area II and Area III shall mean as under :—

Area I—Places with a population of more than 22 lakhs

Area II—All cities other than those included in Area I which have a population of 1 lakh and more

Area III—All places not included in Area I and Area II.

(j) Regulation 23(i) shall read as under :—

On and from 01-11-1987, if he is serving in a place mentioned in Column I of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in Column 2 thereof against that place, provided that the city compensatory allowance at places in the State of Goa other than urban agglomeration of Panaji and Marmugao, where it was not payable on 01-11-1987 shall be payable with effect from 20-08-1988.

Places	Rates
1	2
(a) Places in Area I and in the State of Goa	6 1/4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 220/- per month
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 135/- per month.

(k) Regulation 23(v) shall read as under :

“On and from 01-11-1987, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may in addition to his pay, draw a deputation allowance of 12% of pay, maximum Rs. 700 and such other allowances as he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place :

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation he shall receive a deputation allowance equal to 6% of his pay, maximum Rs. 350 :

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member or to Banking Service Recruitment Board shall be eligible for deputation allowance at 6% of his pay maximum Rs. 350.”

(l) Regulation 23(vi) shall read as under :—

“On and from 01-11-1987, if he is required to officiate in a post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, subject to a maximum of Rs. 250 p.m. for the period for which he officiates. Officiating Allowance will rank as pay for purposes of Provident fund and not for other purposes.

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.”

(m) Regulation 23(vii) shall read as under :

“On and from financial year 1989/90 if he is posted at a branch where books are closed on 31st March and 30th September a closing allowance of Rs. 150 for each of the two closings.”

(n) Regulation 23(x) shall read as under :

“On and from 01-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of table below, a hill and fuel allowance at the rate mentioned in column 2 thereof :—

Place	Rate
1	2
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Nercara Town	5% of pay subject to a maximum of Rs. 130/-
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	6 1/2% of pay subject to a maximum of Rs. 160/-
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	15% of pay subject to a maximum of Rs. 600/-

Note.—(a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, will be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centres with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn. The allowance already paid between 01-11-1987 and 30-04-1989 shall not be recovered. From 1st May, 1989 onwards the quantum of allowance paid as on 30th April under the old provisions alone shall be protected in the case of officers posted at that centre on or before that date till the time they remain posted at that centre in the same scale of pay.”

(o) Regulation 24(1) shall read as under :

“An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :—

(a) Medical Expenses.—On and from 01-01-1990 reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :

TABLE

Pay Range	Reimbursement limit p.m.
1	2
Rs. 2100/- to Rs. 3060/-p.m.	Rs. 750/-
Rs. 3061/-p.m. and above	Rs. 1000/-

NOTE.—An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.



**Explanation :**

"FAMILY" of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

(b) Hospitalisation Expenses.—(i) On and from 01.04.1989, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 90 per cent in the case of an officer and 60 per cent in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc., of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the Government.

(ii) The officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal Hospital or any private hospital i.e. hospitals under the management of a Trust, Charitable institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the Bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 01.04.1989, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 90 per cent in case of an officer and 60 per cent in the case of his family members :—

Cancer, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac Ailment, Tumor, Small Pox, Pleurosy, Diptheria, Leprosy, Kidney Ailment."

(p) Regulation 25 shall read as under :—

"On and from 01-11-1987, no officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the officer of 6 per cent of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less. Provided that a further sum equal to 1-1/2 per cent of pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the Bank from an officer if furniture is provided at such residence. Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer."

(q) Regulation 33(4) shall read as under :—

"On and from 01-01-1990, Privilege Leave may be accumulated upto not more than 240 days except where leave has been applied for and it has been refused."

(r) Regulation 34(1) shall read as under :—

"On and from 0-1-01-1989, an officer shall be eligible for 30 days of sick leave for each completed year of service subject to a maximum of 18 months during the entire service. Such leave can be accumulated upto 540 days during the entire service, and may be availed of only on production of medical certificate by a medical practitioner acceptable to the bank or at the bank's discretion nominated by it at its cost."

(s) Regulation 35 shall read as under :—

"On and from 0-1-01-1989, where an officer has put in a service of 24 years, he shall be entitled to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of 24 years subject to a maximum of three months of additional sick leave."

(t) Regulation 41 shall read as under :—

"On and from 01-07-1989, the following provisions shall apply whenever an officer is required to travel on duty :—

(1) (i) An officer in Junior Management Grade may travel by 1st Class or AC Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(ii) An officer in Middle Management Grade may travel by 1st Class or AC Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 kms. He may, however, travel by air (economy class) even for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

(iii) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by train AC 1st Class or by air (economy class).

(iv) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kms. However when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.

(v) Any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by the Bank's vehicle.

(2) (i) For air or rail travel, a single fare for the officer will be reimbursed.

(ii) For travel by road by his own vehicle, such rate on a kilometre basis as may be decided by the Bank, from time to time, having regard to the type of vehicle used, the cost to be incurred and the terrain covered, will be reimbursed.

(iii) Where hiring of a taxi is permitted, the actual taxi charges will be reimbursed.

(iv) For travel by public motor or water transport, the actual fare will be reimbursed.

(3) Actual expenses incurred for transport and portage will be reimbursed.

(4) On and from 01-01-1987, an officer in the Grades/ Scales set out in Column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof.

TABLE

Grades/Scales of Officers	Daily Allowance (Rs.)		
	Major 'A' Class Cities	Area-I	Other places
Scale VI & VII	100 00	80.00	60.00
Scale IV & V	100.00	80 00	60 00
Scale II & III	70.00	60.00	50.00
Scale I	70 00	60.00	50.00

Provided that :—

- (a) Where the total period of absence is less than 8 hours, but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.
- (b) Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in ITDC Hotels, subject to the limits as given below :—

Grades/Scale of Officers	Eligibility to stay	Boarding charges (Rs.)		
		Major-A Class Cities	Area-I	Other Places
Scale VI & VII	4* Hotel	100.00	80.00	60.00
Scale IV & V	3* Hotel	100.00	80.00	60.00
Scale II & III	2* Hotel (Non-AC)	70.00	60.00	50.00
Scale I	1* Hotel (Non-AC)	70.00	60.00	50.00

- (c) Where free lodging is provided at the place of halt  $\frac{3}{4}$ th of the halting allowance will be admissible.
- (d) Where free boarding is provided at the place of halt  $\frac{1}{2}$  of the Halting Allowance will be admissible.
- (e) Where free lodging and free boarding are provided at the place of halt,  $\frac{1}{4}$ th of the Halting Allowance will be admissible.
- (f) A supplementary Diem Allowance of Rs. 10 per day of halt outside headquarters on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

Explanation :

For the purpose of computing Halting Allowance 'per diem' shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, "per diem" shall mean a period of not less than 8 hours."

(u) Regulation 42(2)(i) shall read as under :—

"On and from 01-11-1987 an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his

baggage by goods train upto the following limits :—

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 2100/- p.m. to		
Rs. 3060/- p.m.	3000 kgs.	1000 kgs.
Rs. 3061/- p.m. and above	Full Wagon	2000 kgs.

(v) Regulation 42(4) shall read as under :—

"An Officer transferred to any station shall be eligible to claim Halting Allowance for the period spent on journey at the same rates in the case of travel on tour :

Provided that on and from 30-10-1987 where no residential accommodation is made available by the Bank to an officer at the new place of posting and where such an officer may incur additional expenses in the process of taking over charge, for reasons, beyond his control, the Competent Authority may consider, on merit, grant of halting allowance to him upto a maximum period of 15 days or till the time the quarters are made available to him, whichever is earlier."

(w) Regulation 45(2) shall read as under :—

"The Bank shall contribute to the Provident Fund in accordance with the rules governing the Provident Fund, from time to time, provided that the amount contributed by it shall not be more than 10 per cent of 80 per cent of pay on and from 01-11-1987 to 31-12-1988, 10 per cent of 90 per cent of pay on and from 01-01-1989 to 31-12-1989 and 10 per cent of pay on and from 01-01-1990 of the officer."

(x) Regulation 46(2) shall read as under :—

"The amount of Gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 month's pay.

Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of Gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond thirty years.

NOTE.—If the fraction of service beyond completed years of service is six months or more, gratuity will be paid pro-rata for the period.

M. GOPALAKRISHNAIAH, General Manager (P).